Title: Re: Need to restore Old Pension Scheme in Uttar Pradesh.

श्रीमती संगीता आज़ाद (लालगंज): पेंशन एक तरह से बुढ़ापे की लाठी होती है। पुरानी पेंशन स्कीम को खत्म कर दिया गया है जिससे लोगों में भविष्य में कैसे जीवन यापन करेंगे एक अहम मुद्दा बन गया है। इससे सभी सरकारी कर्मचारी चिंतित है। पेंशन के सहारे कर्मचारी शेष जीवन को सम्मान पूर्वक निर्वहन कर लेते थे किंतु केंद्र की "नव-उदारवादी नीतियों" ने देश की सिविल सेवा को भी गहरे संकट में डाल दिया है। नई आर्थिक नीति ने सिविल सेवा के आकार को कम करते हुए, सभी क्षेत्रों से सरकार की वापसी को निर्धारित किया। "आउटसोर्सिंग, अनुबंध और निजीकरण बढ़ रहे हैं। लाखों पद खाली पड़े हैं, जिससे मौजूदा कर्मचारियों के लिए असहनीय काम का बोझ पैदा हो रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए परिभाषित लाभ पेंशन योजना, या ओपीएस, लाभार्थियों से किसी भी आर्थिक योगदान के बिना एक अच्छी तरह से निर्मित और श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सामाजिक सुरक्षा योजना थी। निजीकृत पेंशन योजना अब नव-उदारवादी वैश्वीकरण का सबसे प्रमुख आर्थिक हमला है जिसने दुनिया भर के श्रमिकों और कर्मचारियों को अपनी चपेट में ले लिया है। वर्तमान में केंद्रीय सिविल सेवा में 10 लाख से अधिक पद खाली पड़े हैं। कई राज्यों में स्वीकृत पदों में से लगभग आधे अनुबंधित/आउटसोर्स /दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा भरे गए हैं। अंतिम श्रेणी के पदों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और उच्च पदों पर भी संविदा नियुक्तियां की गईं है। जिस तरह से पुरानी पेंशन की बहाली पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे अन्य राज्यों ने बहाल कर दी ठीक उसी तरह केंद्रीय कर्मचारियों और उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। उत्तर प्रदेश के राज्य कर्मचारी कई सालों से आंदोलन कर रहे हैं और लगभग सभी सांसदों तथा विधायकों को अपना ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। मेरी सरकार से मांग है कि उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए ताकि सभी कर्मचारी अपने जीवन को खुशहाली और सम्मान से जी सकें।